

श्रम एवं रोजगार विभाग की वित्त वर्ष 2006-2007 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय-1

परिचय

श्रम एवं रोजगार विभाग वर्ष,1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है—तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोजगार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड—श्रम,कारखाना एवं रोजगार है। श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 28(केन्द्रीय एवं राज्य) हैं,का प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ता एवं श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय व औद्योगिक अधिकरणों में पूरे समय के लिये दो पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम,1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण,नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यन्वयन किया जाता है।

रोजगार शाखा का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण,मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं

इत्यादि मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम,1959 तथा नियम,1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत सार्वजनिक/ निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार सूचना के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2006-2007 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा बजट विवरण इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दिया गया है।

अध्याय-2

श्रम एवं रोजगार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

श्रम एवं रोजगार विभाग माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की देख रेख में कार्य करता है जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में सचिव(श्रम एवं रोजगार) तथा उप सचिव(श्रम एवं रोजगार) द्वारा सहयोग दिया जाता है।

श्रम एवं रोजगार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार "विभागाध्यक्ष" के रूप में कार्यरत हैं। निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है:-

- 2.1 निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्यश्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप-श्रमायुक्त तथा श्रम-निरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत श्रमायुक्त "मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं तथा संयुक्त- श्रमायुक्त "अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं। अधीनस्थ कार्यालयों में कारखाना अधिनियम,1948 को कार्यान्वित करने के लिये तीन सहायक निदेशक कारखाना कार्यरत हैं।

जिनमें से दो का मुख्यालय शिमला में (दो सहायक निदेशक कारखाना के पदों में से एक पद 1.5.2004 से रिक्त है और इसका कार्यभार मुख्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक कारखाना देख रहे हैं) तथा एक का मुख्यालय ऊना में स्थित है । इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है:-

1. सहायक निदेशक कारखाना-शिमला
2. जिला-शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्धी, बरोटीवाला, नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)
3. सहायक निदेशक कारखाना, ऊना
जिला-कांगडा, चम्बा, ऊना हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, लाहौल स्पीति, सिरमौर तथा बद्धी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र, जिला सोलन।

इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोजगार से सम्बन्धित कार्य-कलापों के लिये श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार की देख-रेख में उप-निदेशक रोजगार, रोजगार बाजार सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थापना (विशेष रोजगार कार्यालय अपंगों हेतु), राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन अधिकारी तथा रोजगार अधिकारी (केन्द्रीय रोजगार कक्ष) आवेदकों को रोजगार सहायता उपलब्ध करवाने तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन हेतु सहायता करते हैं।

2.2 श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण । श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं । श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.श्रम अधिकारी,शिमला | उप-मण्डल(शहरी एवं ग्रामीण),उप मण्डल चौपाल एवं ठियोग तहसील |
| 2. श्रम अधिकारी,रामपुर | रामपुर,रोहडू तथा डोडरा-क्वार उप-मण्डल तथा कुमारसैन तहसील |
| 3. श्रम अधिकारी, सोलन | उप-मण्डल सोलन,कण्डाघाट,अर्की तथा कसौली तहसील(बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर) |
| 4. श्रम अधिकारी,बद्धी | तहसील नालागढ,औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला |
| 5. श्रम अधिकारी,नाहन | जिला सिरमौर |
| 6. श्रम अधिकारी,मण्डी | जिला मण्डी |
| 7. श्रम अधिकारी,कुल्लु | जिला कुल्लु,उदयपुर तथा केलांग उप-मण्डल |
| 8. श्रम अधिकारी, किन्नौर | जिला किन्नौर,उप मण्डल काजा |
| 9. श्रम अधिकारी,धर्मशाला | जिला कांगडा |
| 10. श्रम अधिकारी,चम्बा | जिला चम्बा |
| 11. श्रम अधिकारी,बिलासपुर | जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर |
| 12. श्रम अधिकारी,उना | जिला उना |

(ख) कारखाना अधिनियम,1948 के अन्तर्गत प्रदेश को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से दो खण्डों का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि तीसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोजगार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोजगार कार्यालय तथा 55 उप-रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला	कुमारसैन, मशोबरा, ठियोग, रामपुर-बुशैहर, रोहडू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी।
2	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, मण्डी	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, तथा गोहर।
3	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर, ज्वाली, नुरपुर, लम्बागांव, नगरोटा सूरियो, बैजनाथ, इन्दौरा, बडोह, देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा।
4	विश्वविद्यालय सूचना एवं ब्यूरो, शिमला	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है।
5	विश्वविद्यालय सूचना एवं ब्यूरो, विश्वविद्यालय, पालमपुर	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है।
6	जिला रोजगार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा, सलूणी स्थित सुन्दला।
7	जिला रोजगार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर।
8	जिला रोजगार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवी एवं श्री नैना देवी जी
9	जिला रोजगार कार्यालय, कुल्लु	बंजार एवं आनी
10	जिला रोजगार कार्यालय, सोलन	नालागढ, अर्की एवं कसौली
11	जिला रोजगार कार्यालय, सिरमौर स्थित नाहन	पांवटा-साहिव, राजगढ, शिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
12	जिला रोजगार कार्यालय, लाहौल स्पिति	काजा एवं उदयपुर

	स्थित केलौंग	
13	जिला रोजगार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पिओ	पूह एवं निचार
14	जिला रोजगार कार्यालय, ऊना	अम्ब

2.3 वर्ष 2006–2007 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति / नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण:

सेवानिवृत्तियों का ब्यौरा:

कमांक	सेवानिवृत्त कर्मचारी की संख्या	श्रेणी
1.	2	अधीक्षक ग्रेड-I
2.	1	निजी सहायक
3.	1	श्रम निरीक्षक
4.	1	दफतरी
5.	1	चतुर्थ श्रेणी

सरकार की अनुमति से श्रम न्यायालय एवं औधौगिक अधिकरण में अनुबन्ध आधार पर की गई नियुक्तियों का ब्यौरा:

कमांक	नियुक्तियों की संख्या	कर्मचारी की श्रेणी
1.	1	लिपिक
2.	1	आशुटंकक

नव-सृजित श्रम कार्यालयों में नियुक्तियों का ब्यौरा:

क्रमांक	नियुक्तियों की संख्या	कर्मचारी की श्रेणी
1.	2	लिपिक
2.	1	श्रम निरीक्षक
3.	1	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
4.	6	अशंकालिक कर्मचारी
5.	1	चालक (अनुबन्ध आधार पर)

पदोन्नतियों का ब्यौरा:

क्रमांक	पदोन्नतियों की संख्या	श्रेणी
1.	4.	श्रम अधिकारी
2.	1	निजी सहायक
3.	2	अधीक्षक ग्रेड-1A
4.	6	वरिष्ठ सहायक
5.	6	श्रम निरीक्षक
6.	3	चतुर्थ श्रेणी

अतिरिक्त प्रवीणता वेतन वृद्धियों का ब्यौरा:

क्रमांक	प्रवीणता वेतन वृद्धियों की संख्या	श्रेणी
1.	11	तृतीय
2.	7	चतुर्थ

सात नये श्रम कार्यालय (कर्मचारियों सहित) 20.7.2006 को सृजित करवाये गये।

विभाग द्वारा निम्न श्रेणियों की वरिष्ठता सूचियां जारी की गई:—

वरिष्ठ सहायक,सांख्यिकीय सहायक, चपडासी ।

प्रशासनिक विभाग को निम्न श्रेणियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधन के लिए भेजे गए:—

वरिष्ठ आशुलिपिक ।

2.4. श्रम एवं रोजगार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौरा:

श्रम एवं रोजगार विभाग में कुल 422 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 144 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार(भा.प्र.से.)	1	—
2	पीठासीन अधिकारी	2	—
3	संयुक्त श्रमायुक्त	1	—
4	उप श्रमायुक्त	1	—
5	उप निदेशक रोजगार	1	—
6	सहायक निदेशक कारखाना	3	1
7	श्रम अधिकारी	12	3
8	विधि सहायक	1	1
9	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	1
10	श्रम निरीक्षक	33	9
11	सिलाई अध्यापिका	1	1
12	चालक	5	—
13	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी	8	8
14	जिला रोजगार अधिकारी	10	.
15	रोजगार अधिकारी	12	3
16	अधीक्षक ग्रेड-1	1	—
17	अधीक्षक ग्रेड-11	12	2

18	निजि सहायक	1	—
19	सांख्यकीय सहायक	14	2
20	वरिष्ठ सहायक	62	3
21	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1
22	आशुटंकक	4	1
23	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	128	57
24	दफ्तरी	4	1
25	कम्प्यूटर आप्रेटर	1	.
26	चैकीदार	12	2
27	चपड़ासी	83	47
28	सफाई कर्मचारी	5	1
29	फ़ाश	1	—
	जोड़	422	144

अध्याय—3:

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोजगार खण्ड में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य 28 श्रम अधिनियमों को प्रदेश में लागू करना है। औद्योगिक शान्ति बनाये रखना, मालिकों एवं कामगारों के बीच औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए उचित परामर्श देने की भूमिका निभाना है। इसके अतिरिक्त श्रम खण्ड का मुख्य कार्य संस्थानों में न्यूनतम मजदूरी को लागू करना है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में श्रम खण्ड की कारखाना-शाखा, कारखानों में दुर्घटनायें रोकने और सुरक्षा उपायों को लागू करने बारे भी आवश्यक भूमिका निभाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या वर्तमान में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। समझौता व्यवस्था औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान सात नये श्रम कार्यालय कमशः बिलासपुर, बट्टी, सिरमौर स्थित नाहन, किन्नौर स्थित रिकांग-पिओ, उना, चम्बा व कुल्लू में खोले गये हैं तथा इन कार्यालयों ने अपना काम करना आरम्भ कर दिया है। इन सात नये कार्यालयों में एक-एक श्रम अधिकारी के पद के सृजन की स्वीकृति तथा इनकी सहायतार्थ एक-एक श्रम निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति सरकार द्वारा मिल गई है। उक्त कार्यालयों में कुछ पद पदोन्नति द्वारा भर दिये गये हैं शेष को भरने की प्रक्रिया जारी है।

अब प्रदेश में कुल मिलाकर 12 श्रम कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं जो कि श्रम अधिनियमों को लागू करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं है वहाँ पर जिला रोजगार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहाँ पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी बतौर समझौता अधिकारी औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहाँ पर श्रम अधिकारी, उप श्रमायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त और श्रमायुक्त विवादों को निपटाने में हस्ताक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार हों ऐसी संस्थानों द्वारा वर्कर्स कमेटी का गठन

किया गया है। ये वर्कर्स कमेटियों भी औद्योगिक शान्ति बनाने में काफी सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2006-2007 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है।

31.3.2007 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम,1948	2829	1,46,031
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम,1961	110	7,406
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम,1926	1068	—
4	प्लान्टेशन अधिनियम,1951	22	678
5	बोनस भुगतान अधिनियम,1965	198	20,985
6	प्रसुति अधिनियम,1961	2991	1,47,709
7	अन्तरराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम,1979		
	(क)प्रमुख नियोक्ता	119	34,585
	(ख)ठेकेदार	675	21,056
8	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970		
	(क)प्रमुख नियोक्ता	513	69,134
	(ख)ठेकेदार	2207	62,878
9	म्नीसाना वेज बोर्ड	36	459
10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	2100	80,000
11	उपादान भुगतान अधिनियम,1972	1623	1,35,231

12	कर्मचारी अधिनियम,1952	भविष्य	निधि	5363	2,37,565
----	--------------------------	--------	------	------	----------

न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिर्धारण,न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अन्तर्गत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सितम्बर,2003 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पुर्नगठन किया था । इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 75/-रु० प्रतिदिन या रु० 2250/- प्रतिमाह प्रथम जनवरी,2007 से निर्धारित की है जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 7.7 प्रतिशत अधिक है। अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी (समान अनुपात से) बढ़ोतरी की गई है जो कि दिनांक 1.1.2007 से लागू की गई है, जिन अनुसूचित व्यवसायों में बढ़ोतरी की गई है। वे निम्न प्रकार से हैं:-

1. कृषि
2. सड़क तथा भवन निर्माण पत्थर पिसाई कशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रासपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. कैमिकल्ज तथा कैमिकल्ज प्रोडक्शन
7. इंजिनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा-2 के खण्ड(क)में परिभाषित
10. होटल/रेस्तरा

11 निजि शैक्षणिक संस्थान

इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्य करने वाले मजदूरों के लिये उक्त दरों के उपर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई है । जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को उक्त दरों के उपर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई है । महिला और पुरुष कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है ।

न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को "निरीक्षक" नियुक्त किया है तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को इस अधिनियम के अर्न्तगत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावा का निपटारा कर सकें ।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न-भिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियाँ गठित की हैं:—

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड / समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ निर्धारण बारे सरकार को परामर्श देना
2	समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976	सलाहकार समिति	स्त्रियों को रोजगार अवसरों तथा लिंग के

			आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे सरकार को परामर्श देना
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना व जहाँ रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों सरकार को देना
4	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	राज्य ठेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा ठेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में ठेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिशों देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई. एस. आई.	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य/ पैंशन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धि कार्य करना । क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई. एस. आई. स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम(योजना)1948	स्थानीय समितियाँ	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारू रूप में संचालन तथा कार्यन्वयन

			एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	क्षेत्रीय समिति ई० पी० एफ० हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सुचारु रूप में संचालन तथा कार्यन्यवन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारों को शिक्षा देने बारे।
8	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति(बन्धुआ मजदूरी)	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही।
9	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियाँ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही।

परियोजनाओं में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड / समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड	औद्योगिक शान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।
(ख) परियोजना स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों का परियोजनाओं के लिये गठन	उक्त समिति विभिन्न परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनको पूरा करवाना सुनिश्चित करेगी।
(ग) त्रिपक्षीय राज्य स्तरीय समिति	श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों/ विवरणियों के

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम,1948

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निशुल्क: चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है । यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा बिजली का प्रयोग हो, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शौडों में लागू नहीं होता । जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 10,000/- रुपये से अधिक है वह इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के योगदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में चलाई जा रही है:—

क्रमांक	क्षेत्र	जिला
1.	शिमला नगर निगम क्षेत्र	शिमला
2.	पांवटा साहिव	सिरमौर
3.	काला अम्ब	सिरमौर
4.	सोलन नगर निगम क्षेत्र	सोलन
5.	बद्दी	सोलन
6.	बरोटीवाला	सोलन
7.	नालागढ	सोलन
8.	परवाणु	सोलन
9.	मैहतपुर	ऊना

श्रमिकों के लिये मैहतपुर ,बरोटीवाला,सोलन और बद्दी में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणू में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है । इसके साथ क्षेत्रीय निदेशक ई.एस.आई का कार्यालय परवाणू में (ई.एस.आई कौम्पलैक्स) कार्यरत है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,शिमला में स्थित है। इस योजना के अर्न्तगत कारखानों तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान करता है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 5363 संस्थानों में 2,39,565 कर्मचारियों को लाया जा चुका है ।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

संचालित कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है । कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो । हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है ।

उपादान अधिनियम,1972 के अर्न्तगत अपील का निपटारा

वित्त वर्ष 2006-07(1.4.2006 से 31.3.2007) के दौरान 12 अपील केसों का निर्णय/निपटारा किया गया जिसके अर्न्तगत रू0 7,15,564 (रू0 सात लाख पन्द्रह हजार पांच सौ चौंसठ) बतौर उपादान विभिन्न कर्मचारियों/कामगारों को मुहैया करवाया गया।

वर्ष के अन्त (31.3.2007) में आठ मामले लम्बित रहे।

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना बनाना:

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना बनाई गई है। यद्यपि प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनकी जांच करवाई गई लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में आता हो।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिती का काजा उप-मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण धर्मशाला इस वर्ष स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर,बिलासपुर,मण्डी,कुल्लु तथा लाहौल स्पिती का लाहौल

भाग है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर श्रम अदालत औद्योगिक न्याय अधिकरण के एक एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	2
2	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3	वरिष्ठ सहायक-एवं-रीडर	4
4	अहलमद	4
5	चालक	2
6	दफ्तरी	2
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
8.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
9.	सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	1

इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 33(सी)(2) के अधीन भुगतान दावे बारे आवेदन पत्र सीधे तौर से श्रम न्यायालयों को दिये जा सकते हैं।

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के तहत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को सरकार इन न्यायालयों/अधिकरणों को भेजती है। इसके अतिरिक्त, कामगार अवार्ड,समझौता और भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधेतौर पर दाखिल किये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक अधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि अन्य राज्यों

में श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण अलग-अलग हैं। श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत भी कार्य कर रहे हैं।

ये न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर प्रदेश के मजदूरों को न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि मजदूर दूर-दराज के क्षेत्रों में अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1.4.2006 से 31.3.2007 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	31.3.2006 को लम्बित मामले	1,050	678	1,728
2	1.4.2006 से 31.3.2007 तक प्राप्त मामले	316	377	693
3	31.3.2007 को कुल मामले	1,366	1,055	2,421
4	1.4.2006 से 31.3.2007 तक निपटाये गये मामले	411	594	1,005
5	31.3.2007 को लम्बित मामले	955	461	1,416

कामगारों को पहचान-पत्र प्रदान करना:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों तथा ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक कामगार पहचान-पत्र कामगारों को जारी करेंगे जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 1.5.2006 से 31.3.2007 तक की अवधि के दौरान कुल 69,328 कामगारों को पहचान-पत्र जारी किये जा चुके हैं। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश प्रवासी कामगार अधिनियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशोधन किया जा रहा है जिससे कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये कानूनी प्रावधान हो जायेगा।

सांख्यिकीय रचनायें

श्रम खण्ड की 31.3.2007 तक की उपलब्धियों / कार्यों का ब्योरा नीचे दी गई तालिकों पर वर्णित है ।

विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लंघना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:—

तालिका-1

कमांक अधिनियम 31.3.2007 न्यायालय न्यायालय जुर्माने की

का नाम	तक किये गये निरीक्षण की संख्या	में किये गये चालानों की संख्या	दायर द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	राशि
1 दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	4950	2067	2347	1339309,00
2 वेतन भुगतान अधिनियम,1936	2100	97	49	55100.00
3 न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	2676	240	224	147400.00
4 कारखाना अधिनियम,1948	920	33	12	59500.00
5 मोटर टांसपोर्ट वर्करज अधिनियम,1961	41	.	3	2000.00
6 श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	881	134	173	168300.00
7 समान वेतन अधिनियम,1976	108	.	.	.
8 उपादान भुगतान अधिनियम,1972	347	5	9	28000.00
9 बोनस भुगतान अधिनियम,1965	298	.	1	1000.00
10 प्रसूति लाभ अधिनियम,1961	119	.	.	.
11 हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान(राष्ट्रीय आक्स्मिक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम,1969	460	2	9	750.00
12 चाय बागान अधिनियम,1951	4	.	.	.
13 अर्न्तराज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम,1979	236	51	67	64850.00
14 बाल श्रमिक (निषेद्ध) अधिनियम,1986				

		2287	—	—	—
15	औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947				
	4	1	—	—
	कुल	15553	2630	2887	18,66,209.00

तालिका-2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2007 तक पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.2007 तक लाईसैन्स प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कामगारों की संख्या
1	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	513	69134	2207	62878
2	अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार(रोजगार) विनियम एवं सेवा चर्ते अधिनियम,1979	119	34585	675	21056

तालिका-3

क्रमांक	अधिनियम का नाम	उपादान पिछले अनिर्णित मामले	अदायगी 1.4. 2006 से 31.3. 2007 तक प्राप्त मामले	अधिनियम,1972	कुल 1.4. 2006 से 31. 3.2007 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2007 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनकी ऐपीलेंट आथोर्टि के पास अपील
1	उपादन अदायगी अधिनियम,1972	27	36	631	25	37	1

तालिका-4

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

क्रमांक	31.3.2006 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1468	1.4.2006 से 31.3.2007 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	1859	कुल मांग पत्रों की संख्या	207	समझौते के दौरान धारा 12(3)के तहत निपटाये गये असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	901	31 मार्च 2007 को लम्बित मांग पत्र	751	उद्योगों की संख्या	211	कामगारों की संख्या	2982
---------	---	------	--	------	---------------------------	-----	--	-----	-----------------------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	------

तालिक-5

क्रमांक	औद्योगिक रोजगार(स्टैंडिंग आर्डरज) अधिनियम,1946	अधिनियम के तहत आने वाले संस्थानों में से अधिनियम के तहत आने वाले संस्थान	स्टैंडिंग आर्डरज जिन्हें प्रमाणित करवा लिया गया है।
	583		161

तालिक-6

क्रमांक	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	अधिनियम	31.3.	कामगा	31.3.2007	कामग	कुल	कुल
---------	--	---------	-------	-------	-----------	------	-----	-----

क	के अधीन 2007 रों की के अन्त रों संस्था कामगा बाजारों की के अन्त संख्या में की नों की रों की संख्या में वाणिज्य संख्या संख्या संख्या दुकानों संस्थानों की संख्या	69	43355	14340	9932	17812	53287	32152
---	---	----	-------	-------	------	-------	-------	-------

तालिका-7

क्रमांक	31.3.2006 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2006 से 31.3.2007 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा दिलाई गई धनराशि	सम्बन्धित कामगारों की संख्या	31.3.2007 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1	वेतन भुगतान अधिनियम,1936 218	787	1005	676	2416534.00	860	329
2	हि०प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969 2	36	38	25	25219.00	26	13
3.	हि०प्र०लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम 41	52	93	54	697352.00	286	39
4	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 37	20	57	29	12500.00	32	28

विवादों का ब्यौरा

तलिका-8

कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत दिनांक 1.4.2006 से

31.3.2007 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2006 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2006 से 31.3.2007 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	से	31.3.2007 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	को	1.4.2006 से 31.3.2007 तक पंजीकरण पत्रों के नवीकरण की संख्या	प्रमाण
2529	300		2829		1754	

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के तहत निदेशालय स्तर पर 31.3.2006 को 616 विवाद लम्बित थे। वित्त वर्ष के दौरान 358 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) के अर्न्तगत निदेशालय में प्राप्त हुये, अतः कुल विवाद 974 हो गये। इस वित्त वर्ष के दौरान 309 मामले विभिन्न श्रम न्यायलयों को निर्णय हेतू भेजे गये तथा उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के तहत 187 विवाद निरस्त किये गये, तथा 31.3.2007 को 478 मामले शेष बचे।

अध्याय-4 रोजगार खण्ड

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 55 उप रोजगार कार्यालय कार्यरत है। ये रोजगार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'फौरन इम्पलायमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो' का निदेशालय श्रम एवं रोजगार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 में किए गए कार्य का वर्ष 2006-2007 से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक संख्या	मद	2005-2006	2006-2007
1	पंजीकरण	1,69,623	1,49,012
2	अधिसूचित रिक्तियाँ	4,674	6,132
3	सम्प्रेषण	1,38,092	1,38,661
4	सेवा नियोजन	478	सरकारी 1,388 निजी क्षेत्र 4,739
	सजीव पंजिका	8,16,878	7,56,980

1.4.2006 से 31.3.2007 तक जिलावार रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियाँ	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन		सजीव पंजीका(पंजीकृत आवेदका की संख्या)
					सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	
1	बिलासपुर	10,256	137	12,852	75	78	48,534
2	वम्बा	10,055	488	14,628	61	684	46,033
3	हमीरपुर	11,289	253	11,490	200	245	66,598
4	कांगड़ा	34,339	407	18,061	258	710	1,55,908
5	किन्नौर	6,113	688	3,306	05	200	8,856
6	कुल्लू	2,321	176	2,418	12	12	49,819
7	लाहौल स्पिति	872	318	512	9	.	4,368
8	मण्डी	26,145	146	23,650	132	80	1,16,966
9	शिमला	16,079	86	8,372	58	174	1,07,905
10	सिरमौर	10,116	600	5,611	226	865	48,666
11	सोलन	9,995	1,508	22,943	220	853	46,560
12	ऊना	11,432	1,325	14,818	132	838	57,567
	जोड़	1,49,012	6,132	1,38,661	1,388	4,739	7,56,980

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	40,846
स्नातक	94,856
दसवीं व उपर स्नातक से कम	4,92,351
दसवीं से कम पढे लिखे	1,25,275
अनपढ	3,652
कुल योग	7,56,980

सजीव पंजिका का जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	1,59,705
अनुसूचित जन जाति	29,755
ओ.बी.सी.	80,068

अन्य	4,87,452
कुल योग	7,56,980

स्त्री / पुरुष विभाजन

पुरुष	4,42,742
स्त्री	3,14,238
जोड़	7,56,980

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	6,68,049
ग्रामीण	88,931
जोड़	7,56,980

इंजीनियर

क्र०	मद	सिविल	इलैक्ट्रीकल	मकैनिकल
1	डिग्री होल्डर	650	600	444
2	डिप्लोमा होल्डर	1,845	1,685	1,072
3	सर्टिफिकेट होल्डर(आई.टी.आई.)	45,318		

श्रम एवं रोजगार निदेशालय में स्थापित विशेष रोजगार कार्यालय(अपंगों हेतु),द्वारा वर्ष,2006-2007 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी(स्थापना) के अधीन वर्ष,1976 में विशेष रोजगार कार्यालय(अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त विशेष कक्ष(अपंगों हेतु) धर्मशाला में 1983 से कार्यरत है। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता प्रदान करता है।

समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएँ / रियायतें दी गई है जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य

परीक्षा, उपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की(हाथ तथा बाजु) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट है तथा आरक्षण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रतिशत
1.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण	3 प्रतिशत
2.	महिलाओं के लिये खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व शिलाई कटाई केन्द्रों में आरक्षण	5 प्रतिशत

आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उसके अनुरक्षकों को यात्रा-भत्ता देने का प्रावधान है।

200 रोस्टर प्वाइंट में आरक्षण का निर्धारण निम्न है:-

क्रमांक	श्रेणी	रोस्टर प्वाइंट
1.	दृष्टि दोष अपंग	30 वां व 130 वां
2.	श्रवण एवं वाक अपंग	73 वां व 173 वां
3.	अस्थि अपंग	97 वां व 197 वां

व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं हैं, अधिनियम,1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वाइंट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

1.4.2006 से 31.3.2007 तक 1396 अपंग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया जिसके साथ सजीव पंजिका पर रोजगार सहायता प्राप्त करने हेतु अपंग आवेदकों की संख्या 12545 हो गई है,इस अवधि में 17 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। 41 अपंगों के लिये आरक्षित रिक्तियाँ अधिसूचित हुई हैं। जिसके प्रति 115 अपंग प्रत्याशियों के नाम सम्प्रेषित किए गए हैं।

व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्श:

श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित

राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा शेष तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के सन्दर्भ में आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये:—

1	जिन व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया गया	47,845
2	जिन व्यक्तियों ने पंजीकरण के समय व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया	1,49,012
3	जितने व्यक्तियों ने सामूहिक वार्तालाप में भाग लिया	7,968
4	विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जितने मार्गदर्शन दिये गये	69
5	जिन व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त की	15,623
6	चालू रजिस्टर में जितने पुराने केसों का पुर्वालोकन किया	42,729
7	जितने व्यक्ति व्यावसायिक सूचनाकक्ष में आये	4,519

केन्द्रीय रोजगार कक्ष की गतिविधियाँ:

हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में लगी एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में निदेशालय में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2006—07 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार रोजगार सेवा की एक विशेष सुविधा रोजगार प्राप्ति हेतु तथा इस क्षेत्र

के नियोक्ताओं को योग्य एवं प्रशिक्षित कामगार निशुल्क एवं समयानुसार उपलब्ध करवाने में सहायता करता रहा है । केन्द्रीय रोजगार कक्ष के कार्यकलापों का लेखा जोखा निम्न प्रकार से है :-

1. सजीव पंजिका:

रोजगार कार्यालयों से प्राप्त अनुलिपि कार्डों के आधार पर 31.3.2007 तक 25,856 तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग के आवेदक कक्ष की सजीव पंजिका पर उपलब्ध हैं ।

2. रिक्तियों की अधिसूचना:

1.4.2006 से 31.3.2007 तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा 2892 रिक्तियाँ जो तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग से सम्बन्धित हैं केन्द्रीय रोजगार कक्ष को अधिसूचित की गई हैं ।

3. आवेदकों का सम्प्रेषण:

1.4.2006 से 31.3.2007 तक प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यावसायों में तकनीकी व कुशल वर्ग के 23516 आवेदक केन्द्रीय रोजगार कक्ष द्वारा सम्प्रेषित किये गये ।

4. नियोजन:

1.4.2006 से 31.3.2007 तक प्रदेश के निजी क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में कुल 616 रोजगार के इच्छुक तकनीकी व कुशल आवेदकों को नौकरी पर केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से लगवाया गया ।

विदेशी रोजगार एवं जनशक्ति निर्यात ब्यूरो:

हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कुशल,अर्ध कुशल,एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक प्रार्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत तथा उन्हे पासपोर्ट, विजा एवं

उत्प्रवासी अधिनियम व विनियम के बारे जानकारी उपलब्ध करवाने के उदेश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग में वर्ष,1994 में फोरेन इम्प्लौयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो की स्थापना की गई है। यह ब्यूरो उत्प्रवासी अधिनियम के अन्तर्गत महासंरक्षी उत्प्रवासी, श्रम मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा जनशक्ति निर्यात किए जाने के उदेश्य हेतु पंजीकृत है । इसमें 1705 उम्मीदवारों के नाम पंजीकृत हैं ।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोजगार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं । रोजगार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जिला स्तर पर रोजगार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं । यह कार्यक्रम भारतीय व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है । अन्य बातों के साथ- साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे यह सूचना ऐच्छिक आधार पर एकत्रित की जाती है । रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हों, से रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य

अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1960 के तहत एकत्रित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की ईकाइयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। रोजगार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई ईकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के कुल 198 निरीक्षण किए गए हैं।

2. रोजगार बाजार सूचना के संगठनात्मक ढांचे का पूर्ण विवरण।

श्रमायुक्त-एवं-निदेशक रोजगार

रोजगार बाजार सूचना अधिकारी

निदेशालय स्तर पर

जिला स्तर पर

सांख्यिकीय सहायक

क्षेत्रीय / जिलारोजगार अधिकारी

सांख्यिकीय सहायक

3. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1960 की उल्लंघना हेतु मै० किमिका ऐग्रो फूडस् लि० उना, जिला उना, हि०प्र० को भी इस निदेशालय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति के अन्तर्गत सम्बन्धित माननीय मुख्य न्यायाधिक-दण्डाधिकारी, न्यायालय उना द्वारा कम्पनी को वर्ष 2006-07 में 1500/- रु० जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत मै० बायोवेडा एक्शन रिसर्च लि० पौन्टा साहिब जिला सिरमौर हि०प्र० को भी निदेशालय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई है, जो कि सम्बन्धित न्यायालय में लम्बित है।

4. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में निम्नलिखित कम्पनीज/ कारखाना को कारण बताओ नोटिस इस निदेशालय द्वारा जारी किया गया है:-

क्रम संख्या	सम्बन्धित रोजगार कार्यालय	नियोक्ता का नाम जिसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	धारा
1	जिला रोजगार कार्यालय, नाहन जिला सिरमौर (हि0 प्र0)	मै0 जे.बी.मिल्स, काला अम्ब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)	4(II)
2.	जिला रोजगार कार्यालय, उना जिला उना (हि0 प्र0)	इन्टरनैशनल कारस् एवं मोटरस् प्रा0 लि0 अम्ब, जिला उना (हि0 प्र0)	-यथो-
3.	उक्त	मै0 सिगुल लैब ईण्डिया लि0 मैहतपुर जिला उना (हि0 प्र0)	-यथो-
4.	उक्त	मै0 फेबा ईलैक्ट्रिकल कारपोरेशन, गगरेट, जिला उना (हि0 प्र0)	4(II) (5)
5.	उक्त	मै0 कैप्सन पोलीकोट ईण्डिया प्रा0 लि0 मैहतपुर जिला उना (हि0 प्र0)	4(II)
6.	उक्त	मै0 डी.जे. बायोटेक प्रा0 लि0 बेला-बाथरी, जिला उना (हि0 प्र0)	-यथो-
7.	जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)	मै0 गैमन ईण्डिया लि0, C/O कोलडैम हाईड्रो-ईलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट, हरनोरा, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)	4(II) (5)

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त 3/05	3,695	578	2,58,418	58,898
त्रैमासान्त 3/06	3,671	690	2,50,238	65,159

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च 2005

तथा मार्च 2006 में प्रतिष्ठानों की संख्या व अनुमानित रोजगार—

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध-सरकारी केन्द्रीय		अर्ध-सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
03/05	154	17418	2297	172657	615	18679	574	45863	55	3801
03/06	155	15096	2281	167383	623	18529	557	45417	55	3813

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2005 एवं मार्च 2006 में प्रतिष्ठानों की संख्या व अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान 25 या अधिक कर्मचारी वाले		लघु संस्थान 10 से 24 कर्मचारियों वाले	
	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार	प्रति. संख्या	अनु. रोजगार
त्रैमासान्त 03/05	334	54,743	244	4,155
त्रैमासान्त 03/06	409	60,352	281	4,807

नोट:— उपरोक्त सूचना में जिला लाहौल-स्पिती के सितम्बर 1992 तक के आंकड़े सम्मिलित किए गए हैं।

श्रम एवं रोजगार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे

भवनों का विवरण:

श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन वर्तमान में 112 कार्यालय कार्यरत हैं। इसमें से 19 कार्यालय क्रमशः क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मण्डी, जिला रोजगार कार्यालय, चम्बा, नाहन तथा

किन्नौर,श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी तथा रामपुर बुशैहर,श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बढ्डी, नाहन तथा पांवटा साहिब एवं उप रोजगार कार्यालय,रामपुर बुशैहर, नालागढ, भरमौर, व चिडगांव,श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला तथा धर्मशाला सरकारी भवनों में समायोजित है। इसके अतिरिक्त 28 कार्यालय कमशः जिला रोजगार कार्यालय कुल्लु, श्रम एवं रोजगार निदेशालय शिमला, श्रम निरीक्षक कार्यालय कुल्लु, अम्ब, सुन्दरनगर तथा उप-रोजगार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर,बैजनाथ ,पालमपुर,देहरा,इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर,पुह, संगड़ाह,सुजानपुर टिहरा एवं राजगढ तथा सहायक निदेशक कारखाना शिमला,सहायक निदेशक कारखाना, ऊना, जिला रोजगार कार्यालय, ऊना, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला, श्रम अधिकारी कार्यालय धर्मशाला, श्रम निरीक्षक कार्यालय धर्मशाला, विभागीय भवनों में कार्यरत है। इसके साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य आरम्भ किया है इनमें जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर, नाहन, उप-रोजगार कार्यालय उदयपुर, तथा श्रम कार्यालय नाहन, कार्यालयों का कार्य निर्माणाधीन है।

कार्यकुशलता बढाने के लिए कम्प्युटराईजेशन:-

विभाग के कार्य निष्पादन में कार्यकुशलता व पारदर्शिता लाने हेतू समस्त कार्यालयों को कम्प्युट्रीकृत किया जा रहा है। निदेशालय व क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला को कम्प्युट्रीकृत कर दिया गया है। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला में समस्त पंजीकृत आवेदकों के पंजीकरण रिकौर्ड कम्प्युटर पर चढा दिए गए हैं व नए पंजीकरण कम्प्युटर पर किये जा रहे हैं। शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिलों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों के पंजीकरण रिकौर्ड की डैटा एन्ट्री कर दी गई है। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, धर्मशाला व मण्डी एवं जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर,चम्बा,हमीरपुर,कुल्लु,उना में भी रोजगार कार्यालयों की

डैटा एन्ट्री का काम चल रहा है। सभी रोजगार कार्यालयों को कम्प्युट्रीकृत किया जाएगा। इससे पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, योग्य आवेदकों का सम्प्रेषण व रोजगार के आंकडों को संकलन करने का कार्य अतयन्त सरल हो जाएगा। ऐसे ही श्रम व कारखाना खण्डों के कार्यालयों को भी चरणबद्ध रूप में कम्प्युट्रीकृत किया जाएगा।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष में पंजीकृत आवेदकों के रिकौर्ड को भी कम्प्युटर पर चढा दिया गया है। विभाग, एन0आई0सी0, शिमला से इस कक्ष हेतू जौब पोर्टल भी विकसित करवा चुका है। इस जौब पोर्टल का उद्घाटन माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा 1-1-2007 को किया गया है। अब निजी क्षेत्र के नियोक्ता, कुशल कामगारों को अपनी इच्छानुसार व बिना विलम्ब कक्ष से प्राप्त कर पायेंगे।

**4.9. Budget & Actual Expenditure Statement FIGURES
Demand No:27-Labour,Employment & Training.**

S.No.	Head of Account	Sactioned Budget 2006-07		Actual Expenditure during 2006-2007	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.	-	33,85,000	-	33,99,000
2.	01-Labour,101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws.	50,000	81,77,000	46,000	85,42,000
3.	01-Labour,101-Industrial Relations, 03-Wage Board/	-	30,000	-	30,000
4.	01-Labour,102-Working Conditions & Safety, 01-Inspectorate of Factories.	-	2,86,000	-	1,14,000
5.	01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education	-	93,000	-	1,15,000
6.	02-Employment,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Directorate of Employment.	-	19,22,000	-	22,45,000
7.	02-Employment,004-Research ,Survey & Statistics, 01-Collection of EMI	-	28,22,000	-	28,93,000
8.	02-Employment,101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.	6,00,000	2,56,23,000	5,90,000	2,76,68,000
9.	02-Employment,101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.	-	7,06,000	-	6,05,000
10.	02-Employment,101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.	-	1,14,000	-	3,81,000
11.	02-Employment,101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges(Scheduled Castes)	-	2,03,000	-	3,03,000
	Total:	6,50,000	4,33,61,000	6,36,000	4,62,95,000

Centrally Sponsored Schemes (100%)

1.	02-Employment,101-Employment Services, 06-Special Employment Exchanges(Physically Handicapped)	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

Major Works

1.	4250-Capital Outlay on Other Social Services, 00,201-Labour,01-Buildings	43,00,000	-	43,00,000	-
	TOTAL	43,00,000	-	43,00,000	-

BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT RECONSIDERED FIGURE DEMAND NO-31-TRIBAL DEVELOPMENT

1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan,01-Expenditure on inforcement of Labour Laws	50,000	3,76,000	50,000	4,20,000
2	02-Employment,796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employmen Services	2,42,000	22,90,000	2,31,000	21,10,000
	TOTAL	2,92,000	26,66,000	2,81,000	25,30,000

1.	The particulars of its organisation, functions and duties	<p>The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings- Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue the renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.</p>
2.	The powers and duties of its officers and employees.	<p>Cases which are disposed off at the level of <u>Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt/ ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions. iii) Court Cases. iv) Budget, Financial matter/ Expenditure sanctions. v) Publication of Awards.

		<p><u>Deputy Secretary</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) All correspondence relating to personnel matters/ financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action <p><u>Section Officer</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) To supervise all the work relating to personnel/ Budget and public representative etc. ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities. iv) To ensure timely submission of time bound cases/ Court cases. v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date. <p><u>Superintendent</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control. ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority. <p><u>Sr./Jr. Asstt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i) Opening/ maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers. ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of Service Books, Service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and
--	--	--

		<p>other misc. matters.</p> <p><u>Clerk</u></p> <p>i) Diary and despatch/ movement of files weekly & monthly statements etc.</p> <p>ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.</p>
3.	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary the to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./ Under Secretary level. Financial matters/ expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	<p>The various rules & Regulations/ instructions followed are as under:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules, 4. Medical Attendance Rules, 5. Delegation of financial powers. 6. LTC Rules/ GPF Rules/ Pension Rules etc. 7. R & P Rules. 8. Office Manuals.
6.	Statement of the categories of the documents that are	N/A.

	held by it or under its controls.	
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.	N.A.

9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph.No.2621876, 2880735 2. Deputy Secretary.- Ph.No.2628499, 2880527 3.Senior Private Secretary/P.A.-Ph.No.2621876, 2880735 4. Section Officer-Ph.No.2880444 5. Superintendent- Ph.No.2880544 7. Sr. Asstts.-Ph.No. -do- 8. Jr. Asstt.-Ph.No.-do- 9. Clerks-Ph.No. -do- 10. Peon. -Ph.No. -do-
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.

13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department vide Notification dt. 31.10.05 has already designated the officers of the Lab and Employment Deptt. As Appellate Authority/ Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

BY ORDER

**Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of HP**

Endst. No. Shram(A)4-2/2005 dated Shimla-2 the 9th April,2007

Copy to: -

1. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.
2. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimla-2.
3. All the HOD's in HP.
4. All Div. Commissioners,/ DCs in HP
5. The Controller, P & S H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra
(Extra ordinary)
6. Guard File.

**Deputy Secretary (Lab.&Emp.)
to the Government of HP**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :-

Name of Department: **Labour & Employment, Himachal Pradesh**
Govt. of Himachal Pradesh.
Directorate of Labour & Employment.

No: Shram(Prastha)11/05

Dated:21.2.2007

OFFICE ORDER.

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b)of Sec.4 of the Right to Information Act,2005 are as under:-

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its Functions & Duties.

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts(26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act,1959. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, welfare & safety of workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:-

1. Bonded Labour System(Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour(Regulation and Abolition)Act, 1970
3. Child Labour(Regulation and Prohibition)Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act,1981
6. The Building and other construction workers Cess Act,1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
8. Employees State Insurance Act, 1948.

9. Equal Remuneration Act, 1976.
10. Factories Act, 1948.
11. Industrial Dispute Act, 1947.
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity benefit Act, 1961.
16. Minimum Wages Act 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961.
18. Payment of Bonus Act 1965,
19. Payment of Gratuity Act, 1972.
20. Payment of Wages Act 1936,
21. Plantation Labour Act, 1951.
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976.
23. Trade Unions Act, 1926.
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous provisions) Act, 1955
25. Workman Compensation Act, 1923.
26. Boilers Act, 1923

STATE ACTS

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act, 1969
2. H.P. Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick leave) Act, 1969

(II) Powers and duties of Officers and Employees:

Labour Commissioner- cum Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices .Registration of Factories is done under the Factories Act, 1948 and disputes are referred to the two Labour Courts -cum-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala

under the Industrial Disputes Act,1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act,1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of sub-ordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES:

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Shops and Commercial Establishments Act, 1969 .The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws. The Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act,1948.The Certifying Officer under Industrial Employees(Standing Orders)Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act(R&A)Act,1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker

Act,1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes .Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970.Registration Officers and licensing officer under Contract -Labour Act(R&A)Act,1970 and Inter State Migrant Workmen(RECS)Act .Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages ,Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Assistant Director of Factories:

Assistant Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-cum-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. In charges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) **Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:**

All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers. The office of Assistant Director of Factories Una, all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges, District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G. Office from time to time.

(IV) **The norms set by discharge of its function:**

Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) **The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:**

Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) **Statement of the categories of the documents:**

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sr.No.(V)hereinabove. Also files related to Budget, Plan, and Annual Administrative Report etc.

(VII) **The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof;**

- a) State Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.
- b) District Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of respective DCs as Chairman,10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.
- c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1.9.2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30.1.2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.
- d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sep,2003 comprising of Chairman,9 members and member secretary
- e) Regional Board for H.P. Region under ESI Act,1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman,3 members, Ex-Officio member,2 Employees Representative,6 Employers Additional Representative and member Secretary.
- f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman. 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of Employees representatives

- g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI(Gen)Regulation,1950 consisting following members: Chairman, Member ,Labour Inspector, Medical Officer, Incharge 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.
- h) State level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.
- i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman,7 members, Member Secretary.
- j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Chief Minister)112 Members and Member Secretary.
- (VIII)** A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards ,councils ,committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item no (vii) hereinabove meetings are not open to public as such However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) A Directory of Officers and Employees:

	Name	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Sh.Kashmir Chand, IAS	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P.	0177-2025085
2	Sh.S.C.Awasthi	Joint Labour Commissioner, Directorate	0177-2624157
3.	Sh.R.K.Sandhu	Deputy Labour Commissioner, Directorate.	0177-2624305
4	Sh.Manoj Tomar	Deputy Director Employment, Directorate	0177-2624305
5	Smt.Nirmala Sharma	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
6	Mr.K.K.Sharma	District Employment Officer, Mandi	01905-235508
7	Sh.Joginder Singh Patial	District Employment Officer, Kangra	01892-224892
8.	Mr.D.K.Manta.	District Employment Officer, Solan	01792-223746
9	Sh.R.S.Rawat	Officiating District Employment Officer, Sirmour	01702-222274

10.	Ms.Vandna Vaidya	District Employment Officer, Bilaspur	01978-222450
11.	Sh.Prem Singh	District Employment Officer, Kullu	01902-222522
12.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer, Una	01975-226063
13.	Sh.Y.R.Dhiman	District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
14.	Km.Shakuntla Sharma	Officiating District Employment Officer, Chamba	01899-222209
15.	-	CDPO L&S(Holding the Charge of District Employment Exchange, Keylong	01900-222252
16.	--	GM,DIC Holding the Charge of District Employment Exchange Rekong-Peo	01786-222291
17.	Sh.R.P.Rana	Labour Officer, Shimla	0177-2624706
18.	Sh.R.S.Siphayia	Labour Officer, Rampur	01782-234286
19.	Sh.J.S.Negi	Labour Officer, Dharamshala	01892-223745
20.	Sh.T.R.Azad	Labour Office, Solan	01792-235542
21.	Sh.S.K.Kaushal	Labour Office, Mandi	01905-225329

- (X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	Pay Scale
Labour Commissioner-cum-Director of Employment, IAS.	15100-18300
Assistant Director of Factories	12000-16350
Joint Labour Commissioner	10025-15100
Deputy Labour Commissioner	7880-11660
Deputy Director of Employment	7880-11660
District Employment Officers	7880-11660
Regional Employment Officers	7220-11660
Superintendent Grade-I	7220-11660
Labour Officers	7000-10980
Employment Officers	7000-10980
Legal Assistant	6400-10640
Superintendent Grade-II	6400-10640
Personal Assistant	6400-10640
Senior Scale Stenographer	5800-9200

Statistical Assistant	5800-9200
Senior Assistant	5800-9200
Labour Inspectors	5480-8925
Computer Operator	5000-8100
Junior Assistant	4400-7000
Junior Scale Steno	4400-7000
Driver	3330-6200 plus 300 spl.pay.
Steno-typist	3330-6200
Clerk	3120-5160 with initial start of 3220/-
Daftri	2720-4260
Class-IV	2520-4140 (Initial 2620/-)
Frash	2520-4140 (Initial 2620/-)

- (XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans proposed expenditures and reports on disbursement s made;Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.
- (XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes; Not Applicable.
- (XIII) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it;Not Applicable.
- (XIV) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form;Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate , Salary disbursement at Directorate.
- (XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use.The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days ,

especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

(XVI) The names ,designations and other particulars of the Public Information Officers;

(XVII) Such other information may be prescribed and thereafter up date those publications every year:

Annual Administrative Report is printed every Financial Year and is also available on the Departments website, alongwith other information , at Himachal.gov.in/Employment.

Detail of PIO, APIO & Appellate Authority

A	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address
1	Sh.S.C.Awasthi	Joint Labour Commissioner	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building,H.P.Shimla-1
2	Sh.Manoj Tomar	Deputy Director Employment	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building,H.P.Shimla-1
B.Name of the PIO			
1	Smt. Nirmala Sharma	District Employment Officer	Regional Employment Exchange,Shimla-1.
2.	Sh.K.K.Sharma	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Mandi.
3	Sh.Joginder Singh Patial	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Dharamsala.
4.	Sh. D.K. Manta.	District Employment Officer	District Employment Exchange,Solan.
5	Sh.R.S.Rawat	Officiating District Employment Officer	District Employment Exchange Nahan
6.	Ms. Vandana Vaidya	District Employment Officer	District Employment Exchange Bilaspur
7.	Sh.Prem Singh	District Employment Officer	District Employment Exchange Kullu.
8.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer	District Employment Exchange

		Officer	Exchange, Una
9.	Sh.Y.R.Dhiman	District Employment Officer	District Employment Exchange, Hamirpur
10.	Km.Shakuntla Sharma	Officiating District Employment Officer	District Employment Exchange, Chamba
11.	-	CDPO L&S(Holding the Charge of District Employment Exchange, Keylong	District Employment Exchange, L&S
12.	--	GM, DIC Holding the Charge of District Employment Exchange.	District Employment Exchange, Kinnaur
13	Sh.R.P.Rana	Labour Officer	Himrus Bhawan,H.P.Shimla-1
14	Sh.T.R.Azad.	Labour Officer	Labour Office, Solan
15	Sh. R.S.Sipahiya	Labour Officer	Labour Office, Rampur Bushar
16.	Sh S.K.Kaushal	Labour Office	Labour Office, Mandi
17.	Sh.J.S.Negi.	Labour Office	Labour Office, Dharamsala
C: Name of the Appellate Authority			
1)	Sh.Kashmir Chand,IAS	Labour Commissioner-of-cum-Director of Employment, H.P	New Himrus Bhawan, H,.P. Shimla

Application received under the Right to Information Act in 2006-07 = 10

Application dealt under the Right to Information Act in 2006-07 = 9
Application pending under the Right to Information Act in 2006-07 = 1
(under consideration)

